

भारत में ज़मानत की शर्तें

स्रोत: IE

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके तहत उन क्षेत्रों के लिये **संघीय नधियों में कटौती की जाएगी** जहाँ **कैशलेस बेल (नकद रहति ज़मानत)** की अनुमति दी जाती है। इस कदम ने भारत में ज़मानत सुधारों पर नई चर्चाओं को जन्म दिया है।

- **कैशलेस बेल** के तहत, छोटे अपराधों में बिना किसी धनराशि जमा किये रद्दी दी जाती है, बशर्ते अदालत में उपस्थिति होने की शर्तों का पालन किया जाए। इसके विपरीत, पारंपरिक **ज़मानत/बेल में नकद या संपत्ति की ज़मानत** देनी पड़ती है।

भारत में ज़मानत (बेल) की शर्तें क्या हैं?

- **भारत में ज़मानत:** ज़मानत किसी **अभियुक्त की सुनवाई से पूर्व सशर्त रद्दी है**, जो नरिदोष होने की धारणा पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **अभियुक्त न तो फरार हो, न सबूतों से छेड़छाड़ करे और न ही गवाहों को प्रभावित करे**।
 - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023** का अध्याय 35, जिसने **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973** का स्थान लिया है, ज़मानत प्रक्रिया नरिधारित करता है।
- **बॉण्ड (Bond):** यह अभियुक्त द्वारा दिया गया एक लिखित वचन होता है कि वह सुनवाई में उपस्थित होगा और ज़मानत की शर्तों का पालन करेगा। इसके लिये आमतौर पर **नकद राशि** (अपराध और आर्थिक स्थिति के आधार पर राशि) जमा करनी होती है।
- ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर नकद जमा राशि **ज़ब्त** की जा सकती है। मुकदमे के अंत में, परिणाम चाहे जो भी हो, यह राशि वापस की जा सकती है।
- यदि अभियुक्त तत्काल भुगतान नहीं कर सकता, तो अदालत **व्यक्तिगत ज़मानत (PR) बॉण्ड पर रद्दी की अनुमति दे सकती है**, साथ ही नकदी की व्यवस्था करने के लिये समय भी दिया जा सकता है।
- **बेल बॉण्ड:** बेल बॉण्ड किसी तीसरे पक्ष (परिवार, मित्र या नयिकता) की ओर से दी गई गारंटी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त ज़मानत की शर्तों का पालन करेगा और मुकदमे के लिये उपस्थित होगा।
 - प्रतभू एक राशि जमा कर सकता है, जो **अभियुक्त के फरार होने पर ज़ब्त की जा सकती है**। न्यायालय प्रतभू के दस्तावेज़ों, वित्तीय स्थिति और नवास की जाँच करती है तथा कुछ मामलों में **सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट** की भी आवश्यकता होती है।

भारत में जमानत और संबंधित प्रावधान

"जमानत का मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने पर बोझ से संबंधित है, सभी इस बात पर जोर देते हैं कि जमानत का एक विकसित न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।"

-न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर

गिरफ्तारी के लिये संवैधानिक प्रावधान - अनुच्छेद 22: यह अनुच्छेद गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, हिरासत को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

- **दंडात्मक हिरासत:** न्यायालय में मुकदमे और दोषसिद्धि के पश्चात् किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अपराध हेतु दंडित करना।
- **निवारक निरोध:** न्यायालय द्वारा परीक्षण और दोषसिद्धि के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: जमानत को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन जमानती और गैर-जमानती अपराधों को परिभाषित करता है:

अपराध का प्रकार	जमानती	गैर-जमानती
■ CrPC के तहत परिभाषित	अनुसूची 1 में उल्लिखित अपराध, या किसी अन्य कानून द्वारा जमानतीय अपराध	जमानती के अतिरिक्त कोई भी अपराध
■ जमानत देने की शक्ति	अधिकार के रूप में जमानत	न्यायालय/पुलिस का विवेक तथ्यों पर आधारित हो

जमानत बनाम पैरोल बनाम परिवीक्षा

जमानत	पैरोल	परिवीक्षा
■ मुकदमे या अपील की प्रतीक्षा कर रहे प्रतिवादी की अस्थायी रिहाई, न्यायालय में उनकी उपस्थिति की सुनिश्चितता हेतु जमा राशि द्वारा सुरक्षा	जब व्यक्ति को कारावास की सज़ा से कुछ समय की छूट प्रदान की जाती है, उदाहरण के लिये, कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु	किसी अपराधी की सज़ा का निलंबन, किसी अधिकारी की निगरानी में समुदाय में रहने की अनुमति प्रदान करना
■ न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त	पैरोल बोर्ड द्वारा प्रदत्त	न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त

भारत में जमानत के प्रकार

- **नियमित जमानत:** पुलिस हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का न्यायालय का आदेश
- **अंतरिम जमानत:** अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिये आवेदन पर फैसला होने तक न्यायालय अस्थायी अनुतोष प्रदान करती है
- **अग्रिम जमानत:** गिरफ्तारी को रोकने के लिये अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है
- **डिफॉल्ट जमानत:** जब पुलिस निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी करने में विफल रहती है
- **चिकित्सकीय जमानत:** केवल चिकित्सा के आधार पर

जमानत रद्द करना - कुछ आधार पर

- यदि कोई व्यक्ति, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है
- जाँच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है
- साक्ष्यों से छेड़छाड़
- गवाहों को धमकाना, आदि



भारत में जमानत सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

- **आर्थिक असमानता और भेदभाव: नकद और प्रतभू-आधारित जमानत** का प्रभाव गरीब और हाशिये पर रहने वाले वर्गों पर असमान रूप से पड़ता है। कई वचिराधीन कैदी मामूली अपराधों के लिये भी पैसा, संपत्ति या स्थानीय प्रतभू की व्यवस्था नहीं कर पाते।
 - **वधिआयोग (268वीं रपॉर्ट)** का कहना है कि यह संवधान में प्रदत्त समानता और नृषिपक्ष सुनवाई के सिद्धांत का उल्लंघन है।
 - यह गलत धारणा कि सभी अभियुक्तों के पास आर्थिक या सामाजिक संसाधनों तक पहुँच है, 'बेल नॉट, जेल (bail, not jail)' के सिद्धांत को अप्रभावी बना देती है।
- **कमजोर प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपाय:** न्यायालय प्रायः समय पर जमानत देने या उसे अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करने हेतु बनाए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करती। मानकीकृत प्रक्रिया की कमी जमानत देने या न देने में मनमानी करती है।
- **न्यायिक प्रक्रियाओं में विलंब:** मामलों के लंबित रहने और न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ के कारण वचिराधीन कैदियों को मुकदमे से पहले लंबे समय तक अभिरक्षणा में रहना पड़ता है। इन देरी के चलते कई बार अभियुक्त अपने कथित अपराध की संभावित सज़ा से भी अधिक समय जेल में बंदि देते हैं।
 - भारत की जेलों में बंद लगभग 70% कैदी वचिराधीन हैं, जिनमें से कई मुकदमे से पहले महीनों या वर्षों तक जेल में रहते हैं।
- **संवैधानिक और मानवाधिकार उल्लंघन:** जमानत संबंधी प्रथाएँ संवधान के [अनुच्छेद 21 \(जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार\)](#)

तथा अनुच्छेद 14 (वधि के समक्ष समानता) के अनुरूप होनी चाहिये।

◦ अत्यधिक प्री-ट्रायल अभिरक्षा नरिदोषता की धारणा के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

भारत की जमानत प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- जमानत याचिकाओं का समयबद्ध नसितारण: अनावश्यक प्री-ट्रायल अभिरक्षा से बचने के लिये जमानत देने हेतु सख्त समय-सीमाएँ लागू की जानी चाहिये।
 - सतेंद्र कुमार अंतलि बनाम CBI (2022) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि 'बेल नॉट, जेल' सिद्धांत को सामान्य नयिम के रूप में अपनाया जाना चाहिये और समय पर जमानत प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
 - रिपोर्टिंग शर्तें और नगिरानी तंत्र जैसे गैर-अभिरक्षा विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिये। इससे जेलों में भीड़ कम होगी और अपराध की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा।
- वंचित अभियुक्तों के लिये वित्तीय सहायता: जमानत देने में असमर्थ लोगों को धन उपलब्ध कराने हेतु गरीब कैदियों को सहायता (2023) जैसी योजनाओं का वसितार करना।
 - यह गरीबों की असमान रूप से होने वाली कारावास की घटनाओं को कम करता है और संवधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है।
- व्यक्तिगत जमानत के उपयोग का वसितार करना: छोटे और अहसिक अपराधों के लिये व्यक्तिगत सुरक्षा बॉण्ड या गैर-मौद्रिक शर्तों को प्रोत्साहित करना। यह जवाबदेही बनाए रखते हुए वित्तीय बाधाओं के बिना स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
- कानूनी सहायता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा को सुदृढ़ करना: सरल और त्वरित जमानत प्रक्रियाएँ अत्यधिक भीड़ को कम कर सकती हैं, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं तथा गरीबी के अपराधीकरण को रोक सकती हैं।
 - वचिराधीन कैदियों को जमानत प्रक्रिया में सहायता करने के लिये अर्द्ध-कानूनी स्वयंसेवकों और वकीलों को तैनात करना।
 - माधव हयवादनराव होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह नरिणय दिया कि कानूनी सलाह या वकील की सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि कानूनी सहायता प्रदान करना राज्य का दायित्व है, यह कोई दान-धर्म या चैरिटी नहीं है।
- डिजिटल और प्रशासनिक सुधार: जमानत, जमानतदारों और वचिराधीन मामलों के केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखें। सॉल्वेंसी प्रमाण-पत्रों के कारण मुंबई की अदालतों जैसी देरी से बचने के लिये बॉण्ड या जमानतदारों के त्वरित सत्यापन की सुविधा प्रदान करें।

प्रश्न. "जेल नहीं, जमानत": भारत की वर्तमान जमानत प्रणाली के संवैधानिक और मानवाधिकार संबंधी नहितीर्थों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत के संदर्भ मे नमिनलखिति कथनों पर वचिरा कीजिये: (2021)

1. जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।
2. कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिये राज्य सरकारों के अपने नयिम हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

